

नौकरियों में स्थानीय आरक्षण

प्रलिस के लयः

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण, अनुच्छेद 14,16,19, [हरयऱणा राज्य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022](#), आंदोलन की स्वतंत्रता

मेन्स के लयः

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण और नहऱतऱरथ

चरचा में कयों?

पछऱले वरषों की तुलना में नौकरयों में स्थानीय आरक्षण कानून के परणऱमस्वरूप राज्य को नई नऱवऱश परयऱोजनाएँ कम प्रऱप्त हुई हैं, जसऱकी वजह से राषट्र में नई नऱवऱश परयऱोजनाओं में राज्य की हसऱसेदऱरी पछऱले वरष के 3% से घटकर 2022-23 में 1.06% हो गई, जो छह वरषों में सऱसे कम है ।

- हरयऱणा ने वरष 2022 की शुरुआत में [हरयऱणा राज्य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022](#) को लागू कयऱ था, जसऱमें 30,000 रुपए तक ढऱसकऱ वेतन वऱली नऱजी क्षेत्र की नौकरयों में से 75% स्थानीय लोगों हेतु आरक्षणऱतऱ है ।

हरयऱणा राज्य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022:

परचऱयः

- इसके तहत 10 या अधकऱ कऱरुमचऱरयऱओं वऱली फऱरुमों को 30,000 रुपए प्रतऱढऱह वऱली सऱभी नौकरयों में से 75% राज्य के अधऱवऱसी उममीदवारों के लयऱ आरक्षणऱतऱ करने की ऱवशयकता है ।
- इन सऱभी नऱयऱकताओं के लयऱ शऱरुम वऱढऱण, हरयऱणा की ऱधऱकऱरकऱ वेबसाइट पर उपलऱब्ध नऱढऱतऱ पोरटल परसकल ढऱसकऱ वेतन या 30,000 रुपए से अधकऱ वेतन नहऱं पऱने वऱले ऱपने सऱभी कऱरुमचऱरयऱओं को पंजीकृत करना ऱनऱवऱर्य होगा ।

ऱन्य राज्यों में कयऱ गऱ इसी प्रकऱर के प्रयऱसः

- ऱंध्र प्रदेश, ढध्य प्रदेश ऱर ऱरऱरखंड सहऱतऱ ऱन्य राज्यों में ढी नऱवऱसऱयऱओं के लयऱ रोजगार आरक्षण वऱधऱयक ऱथऱवऱ कऱनूनों की घऱषणा की गई है ।
- रोजगार कोटा वऱधऱयक के तहत ऱंध्र प्रदेश के नऱवऱसऱयऱओं के लयऱ तीन-चऱथऱई नऱजी नौकरयऱं आरक्षणऱतऱ हैं, जसऱ वरष 2019 में राज्य की वऱधऱनसऱढऱ दऱवऱरऱ ऱनुढऱदऱतऱ कयऱ गयऱ थऱ ।

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण के लऱढऱ एवं नुकसऱनः

लऱढः

- संवैधऱनकऱ रूप से ढऱन्यः ढऱरतीय संवऱधऱन के अनुच्छेद 16 के तहत अधऱवऱस ऱर नऱवऱस के ऱधऱर पर आरक्षण पर प्रतऱढऱध नहऱं है । यह स्थऱनीय नौकरयऱं में स्थऱनीय लोगों को पहऱले ऱवसर प्रदऱन करने के लयऱ संवैधऱनकऱ रूप से ढऱन्य प्रतऱतऱ होता है कयोंकऱ प्रऱथढऱकऱ तौर पर यहऱ लोग नौकरी सृजन करने वऱली कंढनयऱं के कऱरण पडने वऱले सऱभी प्रतऱकूल प्रऱढऱवों को सहन करते हैं ।
- सढऱनतऱ: स्थऱनीय नौकरयऱं में आरक्षण सढऱज के सऱसे कमजोर वरुग को सढऱनतऱ प्रदऱन करतऱ है, कयोंकऱ आरक्षण केवल नढऱन सतऱर की नौकरयऱं तक ही सीढऱतऱ है ऱर यह ढऱरत के संवऱधऱन के अनुच्छेद 14 के तहत कऱनून के सढऱन संरक्षण की ढऱवऱनऱ के ऱनुसऱर है ।
- ढेरोजगऱरी के लयऱ उपयुक्त सढऱधऱनः ढेरोजगऱरी ऱर स्थऱरऱ रोजगार सृजन की सढऱस्यऱ को देखते हुए स्थऱनीय नौकरयऱं में आरक्षण ऱक उपयुक्त सढऱधऱन है ।
- ढऱरत के संवऱधऱन में अनुच्छेद 371D ऱर E के तहत ऱंध्र प्रदेश ऱर तेलंगऱनऱ राज्यों के लयऱ ऱनकी वऱशऱष परसऱथऱतऱयऱं को देखते हुए नौकरयऱं ऱर शकऱषऱ हेतु वऱशऱष प्रऱवधऱन है । ऱतः ढेरोजगऱरी की स्थऱतऱऱ ढें स्थऱनीय नौकरयऱं में आरक्षण उचऱतऱ ऱर ढऱरत के संवऱधऱन के वऱशऱष प्रऱवधऱनों के ऱनुसऱर उपयुक्त प्रतऱतऱ होता है ।

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** जब कंपनियों स्थानीय लोगों को काम पर रखती हैं, तो वे अपनी कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करती हैं, जो रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास में मदद कर सकता है।
 - स्थानीय लोगों को काम पर रखने का मतलब है कि कंपनियों को कर्मचारियों के स्थानांतरण का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। यह उनकी परचालन लागत को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे कम कीमतों के रूप में ग्राहकों पर डाला जा सकता है।
 - **उत्पादकता में सुधार:** स्थानीय कर्मचारियों की स्थानीय भाषा, संस्कृति और कारोबारी माहौल से परिचित होने की अधिक संभावना है, जो उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **चर्चाएँ:**
- **नविशकों के पलायन में वृद्धि:** यह ऑटो, आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़े घरेलू और बहुराष्ट्रीय नविशकों के पलायन को गति प्रदान कर सकता है जो अत्यधिक कुशल जनशक्ति पर निर्भर हैं।
 - हरियाणा के मामले में वर्ष 2022 में कया गया नविश लगभग 56,000 करोड़ रुपए से 30% गरिकर 39,000-करोड़ रुपए हो गया, स्थानीय आरक्षण कानून के कारण यह वर्ष 2022-23 में नई नविश परियोजनाओं के मामले में नौवें सर्वश्रेष्ठ राज्य से 13वें स्थान पर पहुँच गया।
 - **मौजूदा उद्योगों को प्रभावित करना:** राज्य के अन्य क्षेत्रों से राज्य में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही को रोकने एवं स्थायी नविसियों के मुद्दे उठाने से राज्य में मौजूदा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - यह तकनीकी दक्षिणों और अन्य उद्योगों को अपना आधार हरियाणा से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने तथा राज्य के मौद्रिक संसाधनों को कम करने में भूमिका निभा सकता है।
 - **कुशल प्रतभा की कमी उत्पन्न कर सकता है:** गति और प्लेटफॉर्म कंपनियों पर आरक्षण लागू करने से प्रतभा की कमी हो सकती है।
 - **संवधान के विरुद्ध:** भारत का संवधान अनेक प्रावधानों के माध्यम से देश में कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता और रोजगार की गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद 14 जन्म स्थान पर ध्यान दयि बनिा कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है।
 - अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में जन्मस्थान आधारित भेदभाव की गारंटी नहीं देता है।
 - अनुच्छेद 19 सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं।

आगे की राह

- आरक्षण नीतिको इस तरह से लागू किया जा सकता है जिससे देश में जनशक्ति संसाधनों के मुक्त आवागमन में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीतिकी समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कलिया गया कोई भी नीतित नरिण्य भारत के संवधान के अनुपालन में है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
- स्थानीय लोगों के लिये नौकरी (JRFL) हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के पर्याप्तों का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है और कौशल प्रशिक्षण तथा उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिये पर्याप्त नौकरी के अवसर प्रदान करना है, जो मुख्य क्षेत्रों के रूप में जनता को मुफ्त बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: द हट्टि